

आवश्यकता है

दैनिक प्रभात परिक्रमा

समाचार पत्र को प्रदेश के

सभी जिलों एवं तहसील स्तर

पर संचाल्यता एवं एजेंटों की

आवश्यकता है

संपर्क :

9425023929

सीएम शुभेंदु के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में खराब मौसम के कारण मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान के दौरान मौसम बिगड़ने पर पायलट ने सुझबुझ का परिचय देते हुए पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट में हेलीकॉप्टर की सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग कराई। गंभीरमत यह रही कि इस घटना में मुख्यमंत्री समेत सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दमदम से हेलीकॉप्टर के जरिए केशपुर के लिए रवाना हुए थे। उड़ान के दौरान रास्ते में अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। खराब दृश्यता और संभावित जोखिम को देखते हुए, पायलट ने किसी भी तरह का खतरा मोल न लेते हुए एहतियात के तौर पर कोलाघाट के एक खुले मैदान में सुरक्षित लैंडिंग करने का फैसला किया।

ट्रम्प की मीडिया कंपनी को 2200 करोड़ रुपए का घाटा

3 महीने में सिर्फ 16 करोड़ की कमाई, 6 महीने में 6 हजार करोड़ का नुकसान

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मीडिया कंपनी ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप (टीएमटीजी) को अप्रैल-जून 2026 में 2,261 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस दौरान कंपनी की कुल कमाई सिर्फ 16.15 करोड़ रुपए रही। जनवरी से जून 2026 के बीच टीएमटीजी का कुल नेट लॉस 6,118 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी की कुल कमाई सिर्फ 23.75 करोड़ रुपए थी। यानी छह महीने में कंपनी का घाटा उसकी कुल कमाई से करीब 258 गुना रहा। कंपनी ने अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) को दी रिपोर्ट में बताया कि तीन महीने का घाटा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले काफी बढ़ा है। डिजिटल एसेट्स से 1,800 करोड़ का नुकसान



टीएमटीजी के घाटे की सबसे बड़ी वजह डिजिटल एसेट्स और शेयरों की कीमत में गिरावट रही। इनकी वैल्यू घटने से कंपनी ने करीब 1,809 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया। इसके अलावा 111 करोड़ रुपए ब्याज और 77 करोड़ रुपए शेयर आधारित भुगतान का खर्च आया। वहीं, कंपनी की कमाई बेहद कम रही। अप्रैल-जून

में करीब 13.6 करोड़ रुपए विज्ञापन और 1.7 करोड़ रुपए सब्सक्रिप्शन से मिले। टीएमटीजी का मुख्य प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल है। इसके अलावा कंपनी ट्रुथ+ वीडियो स्ट्रीमिंग और फिनटेक कारोबार चलाती है। पिछले एक साल में कंपनी ने क्रिटोकरेंसी कारोबार में भी विस्तार किया है। ट्रुथ सोशल की विजिट एक तिहाई से ज्यादा घटी ट्रम्प ने 2022 में ट्रुथ सोशल शुरू किया था। यह उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन यह एक्स और फेसबुक जितना बड़ा नहीं बन पाया है। ऑनलाइन ऑकड़े जुटाने वाली कंपनी सिमिलरवेब की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि जुलाई 2026 में ट्रुथ सोशल की वेबसाइट पर आने वाले लोगों की संख्या पिछले साल के मुकाबले एक तिहाई से ज्यादा घट गई।

पहली फील्ड पोस्टिंग में ही 1 करोड़ की रिश्तत

ट्रेनी आईपीएस राहुल बंसल पर सीबीआई कोर्ट सख्त

अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ के जीडीपी और सीबीआई निदेशक से एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगी है

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ फैडर के 2022 बैच के ट्रेनी आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल की पहली फील्ड पोस्टिंग ही गंभीर आरोपों के घेरे में आ गई है। दिल्ली की राजज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत में उनके खिलाफ एक साइबर प्रॉड केस को कथित तौर पर रफ्त-रफ्त करने के बदले 1 करोड़ रुपये की रिश्तत लेने की शिकायत पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ के जीडीपी और सीबीआई निदेशक से एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगी है। राहुल बंसल इससे पहले आयकर विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। आईपीएस में चयन के बाद उनकी पहली



फील्ड पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सीएसपी के तौर पर हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान एक साइबर प्रॉड मामले को खत्म करने या रफ्त-रफ्त करने के लिए कथित तौर पर 1 करोड़ रुपये की मांग की

गई और रकम हवाला के जरिए पहुंचाई गई। 50-50 लाख की दो किस्तों में रकम देने का आरोप शिकायतकर्ता के मुताबिक, कथित 1 करोड़ रुपये एकमुश्त नहीं बल्कि मई 2026 में दो अलग-अलग किस्तों में 50-50 लाख रुपये के

रूप में ट्रांसफर किए गए। शिकायत में इन लेन-देन के लिए हवाला माध्यम इस्तेमाल किए जाने का दावा किया गया है। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष कथित डिजिटल साक्ष्य भी पेश किए गए हैं।

केवायसी बनी जी का जंजाल: गैस कंपनियां उपभोक्ताओं को भेज रही मैसेज...16 तक ई-केवाईसी करा लें, नहीं तो घरेलू सिलेंडर बंद, उधर, गरीब राशन कार्ड धारकों को नहीं मिल रहा अनाज

केवायसी के नाम पर उपभोक्ताओं से हो रही वसूली और लूट!

कहीं 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर घरेलू गैस सिलेंडर बंद होने का मैसेज पहुंच रहा है

भोपाल। केवायसी कराओ... नहीं तो गैस बंद! केवायसी कराओ... तभी राशन मिलेगा! मध्यप्रदेश में केवायसी अब सुविधा कम और उपभोक्ताओं के लिए जी का जंजाल ज्यादा बनती जा रही है। रसोई गैस सिलेंडर से लेकर सरकारी राशन तक, आधार और केवायसी के नाम पर गरीब और आम उपभोक्ताओं को परेशान किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। कहीं 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर घरेलू गैस सिलेंडर बंद होने का मैसेज पहुंच रहा है तो कहीं केवायसी कराने पहुंचे उपभोक्ता को कथित निगम का हवाला देकर गैस पाइप थमाई जा रही है। आरोप है कि इसके बदले बिना बिल 190 से 200 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। सबसे गंभीर स्थिति सरकारी राशन दुकानों पर बताई जा रही है। राशन लेने पहुंचे पात्र परिवारों से परिवार के हर सदस्य की केवायसी कराने को कहा जा रहा है। मजदुरी करने वाले परिवारों के



सामने पूरे परिवार को लेकर दुकान तक पहुंचना मुश्किल है। आरोप है कि किसी सदस्य की केवायसी नहीं होने पर कई जगह राशन देने से इनकार किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस केवायसी का मकसद फजीवाड़ा रोकना और पात्र व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचाना है, वही प्रक्रिया गरीब के लिए परेशानी और वसूली का जरिया कैसे बन गई? प्रदेश में करीब 1.73 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता बताए गए हैं। इनमें से लगभग 39.84 लाख यानी 22.21 प्रतिशत उपभोक्ताओं का सत्यापन बाकी है। गैस कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी जल्द पूरी कराने के संदेश भेजे जा रहे हैं। भोपाल में

भी करीब 7.55 लाख घरेलू गैस उपभोक्ताओं में 1.94 लाख को ई-केवाईसी बाकी बताई गई है। यही वजह है कि केवायसी कराने के लिए गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ बढ़ रही है। उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने की सलाह दी जा रही है। संदेशों में समय पर सत्यापन नहीं कराने पर घरेलू गैस आपूर्ति बाधित होने या कनेक्शन बंद होने जैसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से कमर्शियल सिलेंडर ही मिलेगा, इसका स्पष्ट आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है।

947 रुपए का सिलेंडर कहीं 2935 रुपए का न पड़ जाए

फिलहाल दिए गए आंकड़ों के अनुसार 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 947.50 रुपए, जबकि 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2935 रुपए बताई गई है। यानी घरेलू कनेक्शन की पात्रता प्रभावित हुई तो गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार की रसोई पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है।

केवायसी कराने गए तो पाइप क्यों जरूरी?

सबसे बड़ा सवाल गैस एजेंसियों पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि केवायसी कराने पहुंचने पर उन्हें तथाकथित नियमों का हवाला देकर गैस पाइप लेने के लिए कहा जा रहा है और इसके बदले 190-200 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। शिकायत इससे भी गंभीर इसलिए है क्योंकि आरोप है कि कई मामलों में बिल तक नहीं दिया जा रहा। यदि केवायसी के लिए गैस पाइप खरीदना अनिवार्य नहीं है।

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति वॉर क्राइम के दोषी पाए गए

असद को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

नई दिल्ली। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को सीरिया की एक अदालत ने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर असद और उनके छोटे भाई माहेर को मौत की सजा सुनाई। यह सजा उन्हें सीरिया के 14 साल लंबे संघर्ष के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए सुनाई गई है। इस संघर्ष में लगभग पांच लाख लोग मारे गए थे। सजा सुनाते वक्त अशद कोर्ट में मौजूद नहीं थे। सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद बशर अल असद रूस में निर्वासित जीवन गुजार रहे हैं। इसी मामले में असद के ममेरे भाई आंतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई। नजीब पर



दक्षिणी प्रांत दारा में कार्रवाई का नेतृत्व करने का आरोप था, जिसके कारण विद्रोह हुआ और बाद में गृह युद्ध छिड़ गया। कड़ी सुरक्षा के बीच जब जज सजा सुना रहे थे, तब नजीब कैदी की वर्दी पहने हुए एक पिंजरे के अंदर खड़ा था। दिसंबर 2014 में विद्रोहियों के दमिश्क में घुसने के बाद

असद और उनके भाई माहेर रूस भाग गए थे। बाद में नजीब को हिरासत में ले लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया; वह इस तरह के मुकदमे का सामना करने वाले सबसे ऊंचे ओहदे वाले अधिकारियों में से एक थे। नजीब सीरियाई सेना के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल हैं, जो 2011 में असद के शासनकाल के दौरान दक्षिणी सीरिया के दारा प्रांत में पॉलिटिकल सिक्योरिटी ब्रांच के प्रमुख थे। असद ने सत्ता 2000 में अपने पिता हाफेज अल-असद की जगह ली और दिसंबर 2024 में सत्ता से हटाए जाने तक सीरिया पर शासन किया। उनके पिता ने लगभग तीन दशकों तक देश पर शासन किया था।

जैसलमेर में स्कूल बस में आग लगी

जैसलमेर। जैसलमेर में मंगलवार सुबह 6:30 बजे चलती स्कूल बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस में 17 बच्चे सवार थे। इंजन से धुआं उठते ही ड्राइवर ने तुरंत बस रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद कुछ ही मिनट में बस आग का गोला बन गई। हादसा सदर थाना इलाके के धऊवा गांव के पास हुआ। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। आग बुझने तक बस जलकर कबाड़ हो चुकी थी। गंभीरत रहीं कि किसी बच्चे को चोट नहीं आई। हालांकि बच्चों के स्कूल बैग, कॉपी-किताबें और बस में रखा अन्य सामान जल गया।

पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को नोटिस

पूछा- अब तक कितनी अपीलों का हुआ निपटारा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने आयोग से विशेष रूप से यह बताने को कहा है कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में कितने मामले दायर किए गए, उनमें से कितने मामलों का निपटारा हो चुका है और कितने अभी लंबित हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची



और जस्टिस पी. मोहना की पीठ ने मामले को 25 अगस्त को लंबित मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल अपीलों की

संख्या बताना पर्याप्त नहीं होगा। चुनाव आयोग को यह भी बताना होगा कि अब तक कितनी अपीलों पर फैसला हुआ और उनके क्या परिणाम रहे। सिर्फ अपीलों की संख्या बताना पर्याप्त नहीं

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने चुनाव आयोग से कहा कि अदालत को निपटारा गए मामलों की वास्तविक संख्या और उनके परिणाम की जानकारी चाहिए। अदालत का मुख्य जोर इस बात पर रहा कि एसआईआर से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए बनाए गए अपीलीय तंत्र की प्रभावशीलता कितनी है। पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि कितने लोगों ने मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील की, कितने मामलों पर निर्णय दिया गया और कितने मामले अभी विचाराधीन हैं। अदालत का मानना है कि प्रभावित मतदाताओं को समय पर राहत मिलना जरूरी है।

अपीलीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था पर भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण के मौजूदा ढांचे और उसके कामकाज पर भी पुनर्विचार की जरूरत बताई। जस्टिस बागची ने कहा कि व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भविष्य में कई उपाय किए जा सकते हैं। इनमें न्यायाधीशों तक ऑनलाइन पहुंच जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं, जिससे प्रभावित लोगों को अपनी शिकायतों और अपीलों के निपटारे के लिए अधिक सुविधाजनक व्यवस्था मिल सके। नाम हटाने से ज्यादा अपीलों के निपटारे पर जोर अदालत ने साफ किया कि फिलहाल उसका मुख्य फोकस इस बात

पर नहीं है कि मतदाता सूची से किस व्यक्ति का नाम हटाया गया या किसका नाम बरकरार रखा गया। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन लोगों के नाम एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें अपनी आपत्ति और अपील दर्ज कराने तथा उसका समयबद्ध निपटारा कराने का प्रभावी अवसर मिले। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब चुनाव आयोग को अगली सुनवाई में अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित और निपटारे गए मामलों का विस्तृत ब्यौरा देना होगा। 25 अगस्त को होने वाली सुनवाई में अदालत इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की दिशा तय कर सकती है।

संपादकीय

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर डिजिटल वर्ल्ड को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अमेरिकी अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी पर 5000 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कंपनी को बच्चों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म में बदलाव करने के लिए कहा है।बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे असर को लेकर अमेरिका की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट

कंपनी मेटा पर करीब 5,390 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने पिछले साल 60 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी। ऐसे में जुर्माने की रकम से ज्यादा महत्वपूर्ण अदालत का यह आदेश है कि कंपनी को बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने प्लैटफॉर्म में बदलाव करने होंगे।नाकाम रही कंपनी। न्यू मैक्सिको की अदालत ने माना कि सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। इन प्लैटफॉर्म

को जानबूझकर इस तरह से डिजाइन मेट किया गया है कि बच्चों को इसकी लत लग जाए। नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने में भी कंपनी नाकाम रही है। यूएस में लगा जुर्माना-की रकम का एक हिस्सा पीड़ितों पर खर्च करने का आदेश दिया है, जो बताता है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकतीं। उनकी वजह से समाज में जो परेशानी शुरू हुई है, उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी।

किसी सोशल मीडिया कंपनी को पहली बार इस तरह कटघरे में खड़ा होना पड़ा है और मेटा के लिए परेशानी की बात यह है कि अमेरिका के कई और राज्यों में भी इसी तरह के मुकदमे चल रहे हैं। इससे पहले मार्च में भी मेटा पर 3500 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगा था। गैर-कानूनी कंटेंट-पूरी दुनिया में यह बहस चल रही है कि बच्चों को किस हद तक सोशल मीडिया इस्तेमाल की अनुमति होनी चाहिए। कई

देशों ने अपने यहां निश्चित उम्र सीमा भी लागू की है। हालांकि इसके साथ जरूरी मुद्दा यह भी है कि सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। भारत में भी मेटा लगातार विवादों में है। पीएम नरेंद्र मोदी के एक विडियो को फेसबुक से हटाए जाने पर उसने माफी मांग ली।यह तकनीकी गलती हो सकती है, पर पेड़ प्रमोशन के जरिये गैर-कानूनी कंटेंट को बढ़ावा देने की बात उसने खुद मानी है। इस साल जुलाई में

केंद्र ने नोटिस भी जारी किया था। बैन उपाय नहीं- अमेरिकी अदालत ने अगले पांच बरसों में मेटा को कई सुरक्षा उपाय अपनाने का आदेश दिया है। इस तरह के कदम बाकी जगहों पर भी उठाए जा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया किसी एक देश तक सीमित नहीं रही। हालांकि यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरी तरह बैन उपाय नहीं है, जरूरत जवाबदेही और नियंत्रण की है।

अगर भारत-पाक युद्ध हुआ तो क्या भारत के खिलाफ अपनी सेना उतारेंगे तुर्की और सउदी अरब ?

(नीरज कुमार दुबे)

वर्तमान हालात को देखें तो सऊदी को चाहिए सुरक्षा, पाकिस्तान को पैसा और तुर्किये को ताकत, इसलिए तीनों एक साथ आ गये हैं। हालांकि इस गठजोड़ को समझने के लिए तीनों देशों के हितों को अलग-अलग देखना होगा। सबसे पहले सऊदी अरब की बात करें तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। नाटो के भीतर जब अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच भरोसे की दरारें गहरी हो रही हैं, ठीक उसी समय पश्चिम एशिया में एक नया शक्ति-केंद्र खड़ा करने की कोशिश शुरू हो गई है। मक्का में तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ऐसा रक्षा समझौता किया है, जिसकी सबसे अहम लाइन में साफ कहा गया है कि तीनों में से किसी एक पर हमला हुआ तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। यही वह बिंदु है, जो इस समझौते को सामान्य सैन्य सहयोग से उठाकर एक संभावित नए क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन में बदल देता है। हालांकि इसे अभी आधिकारिक तौर पर ‘सुन्नी नाटो’ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके भीतर उसकी बुनियादी तस्वीर जरूर दिखाई देने लगी है। देखा जाये तो मक्का में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन का एक मंच पर आना अपने आप में बड़ा संदेश है। खास बात यह है कि यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया पहले ही ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की आग में झुलस रहा है। सऊदी अरब पर ईरान और उसके सहयोगी संगठनों के हमलों का खतरा है। पाकिस्तान अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है और तुर्किये पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका लगातार बढ़ा रहा है। यानी तीनों देश एक-दूसरे की जरूरत बना गए हैं।

क्यों हुआ त्रि-पक्षीय समझौता? – वर्तमान हालात को देखें तो सऊदी को चाहिए सुरक्षा, पाकिस्तान को पैसा और तुर्किये को ताकत, इसलिए तीनों एक साथ आ गये हैं। हालांकि इस गठजोड़ को समझने के लिए तीनों देशों के हितों को अलग-अलग देखना होगा। सबसे पहले सऊदी अरब की बात करें तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। दशकों तक रियाद ने अमेरिकी सुरक्षा छत्रे पर भरोसा किया। लेकिन अब सऊदी नेतृत्व यह मानकर चल रहा है कि बदलती अमेरिकी नीति में किसी एक बाहरी शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। ईरान और उसके सहयोगियों की मिसाइल तथा ड्रोन क्षमता ने इस खतरे को और वास्तविक बना दिया है। ऐसे में सऊदी अरब ने अपना सुरक्षा कवच चौड़ा करना शुरू किया है। पाकिस्तान उसके लिए स्वाभाविक साझेदार है। पाकिस्तानी सेना दशकों से सऊदी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देती रही है और हाल के महीनों में पाकिस्तान ने सऊदी अरब में सैनिकों, लड़ाकू विमानों, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों की मौजूदगी भी बढ़ाई है। वहीं पाकिस्तान की जरूरत बिल्कुल दूसरी है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से निवेश और आर्थिक मदद चाहिए, जबकि तुर्किये से रक्षा तकनीक और सैन्य सहयोग चाहिए। बदले में पाकिस्तान अपनी सेना और परमाणु क्षमता को मुस्लिम दुनिया की सुरक्षा में सबसे बड़ा सैन्य योगदान बताकर अपनी भू-राजनीतिक अहमियत बढ़ाना चाहता है। वहीं तुर्किये की बात करें तो एर्दोगन लंबे समय से अपने देश को सिर्फ नाटो का सदस्य नहीं, बल्कि मुस्लिम दुनिया की एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्किये के पास अत्याधुनिक ड्रोन, रक्षा उद्योग और बड़ी सैन्य ताकत है। पाकिस्तान के साथ उसका रक्षा सहयोग पहले ही तेजी से बढ़ चुका है।

यह गठबंधन किसके खिलाफ है? – अब सवाल उठता है कि यह गठबंधन किसके खिलाफ है? इस सवाल का जवाब हालांकि तीनों देशों ने नहीं में दिया है। तुर्किये ने साफ कहा है कि समझौता रक्षात्मक है, यह किसी खास देश या संगठन को निशाना नहीं बनाता और दूसरे क्षेत्रीय देशों के लिए भी खुला है। लेकिन



अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ दस्तावेज की भाषा नहीं देखी जाती, टाइमिंग भी देखी जाती है। और इस समझौते की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है क्योंकि इस समय ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव चरम पर है। ईरान समर्थित हूती, इराकी मिलिशिया और अन्य समूहों की गतिविधियों ने खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंता बढ़ाई है। दूसरी तरफ इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर में बदल दिया है। इसलिए यह समझौता भले ही ईरान का नाम न ले, लेकिन ईरान के लिए इसका संदेश साफ है कि सऊदी अरब अब अकेला नहीं है। राजनीति

ईरान की बढ़ेगी मुश्किलें – वहीं इस समझौते के बाद ईरान के लिए नई चुनौती खड़ी हो गयी है। तेहरान अब तक पश्चिम एशिया में अपने प्रभाव का बड़ा हिस्सा सहयोगी और प्रॉक्सी संगठनों के नेटवर्क के जरिए कायम करता रहा है। लेकिन यदि सऊदी अरब को पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और तुर्किये की रक्षा तकनीक का समर्थन मिलने लगे तो क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। यही कारण है कि मक्का समझौते को ईरान के खिलाफ सीधा सैन्य गठबंधन नहीं होते हुए भी ईरान के लिए रणनीतिक चुनौती जरूर माना जा सकता है।

इजराइल-अमेरिका को भी संदेश – दिलचस्प बात यह है कि इस गठबंधन का एक और बड़ा संदेश इजरायल के लिए भी है। पश्चिम एशिया में जिस ‘सून्नी धुरी’ की चर्चा लंबे समय से होती रही है, वह अब सिर्फ राजनीतिक अवधारणा नहीं रहना चाहती। साथ ही यह अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है और यह समझौता वाशिंगटन के लिए भी सुखद खबर नहीं है। दरअसल सऊदी अरब और तुर्किये दोनों अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था के पुराने साझेदार हैं। लेकिन यदि यही देश अपनी सुरक्षा के लिए अलग क्षेत्रीय सैन्य ढांचा बनाने लगें तो इसका अर्थ साफ है कि अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर भरोसा कम हो रहा है। यही इस समझौते का सबसे बड़ा दीर्घकालिक रणनीतिक अर्थ हो सकता है।

सून्नी नाटो सिर्फ कल्पना है या हकीकत? – इसके अलावा, यदि मक्का मॉडल सफल होता है और उसमें दूसरे सुन्नी देश शामिल होते हैं, तो पश्चिम एशिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली सुरक्षा व्यवस्था के समानांतर एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा खड़ा हो सकता है। सवाल उठता है कि इसमें और कौन-से देश शामिल हो सकते हैं? इसके जवाब में कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और सीरिया जैसे देशों के नाम संभावित सदस्य के रूप में सामने आ रहे हैं। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि यूएई की कई क्षेत्रीय मुद्दों पर सऊदी अरब और तुर्किये से अलग नीति रही है। साथ ही मिस्र भी किसी ऐसे सैन्य गठबंधन में फंसना नहीं चाहेगा जो उसे सीधे

किसी क्षेत्रीय युद्ध में धकेल दे। वहीं सीरिया अपनी युद्धोत्तर परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ‘सून्नी नाटो’ का विस्तार संभव जरूर है, लेकिन आसान नहीं है। **त्रि-पक्षीय समझौते का भारत पर क्या होगा असर?** – अब सवाल यह है कि इस रक्षा समझौते का भारत पर क्या असर पड़ेगा और अगर भारत-पाकिस्तान के बीच फिर सैन्य टकराव हुआ तो क्या तुर्किये और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और भारत के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? देखा जाये तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान की बढ़ती रणनीतिक क्षमता है। तुर्किये पहले से ही पाकिस्तान का करीबी सैन्य साझेदार है और कश्मीर से लेकर रक्षा सहयोग तक उसका रुख भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। 2025 के भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव में भी अंकारा ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। ऐसे में भविष्य में पाकिस्तान को तुर्किये से ड्रोन, हथियार, तकनीक, खुफिया सहयोग और सैन्य सहायता का अधिक संगठित समर्थन मिल सकता है। हालांकि सऊदी अरब को तुर्किये के साथ एक ही नजर से देखना सही नहीं होगा क्योंकि रियाद के पाकिस्तान से गहरे रक्षा संबंध जरूर हैं, लेकिन भारत भी उसके लिए ऊर्जा, व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग का अहम साझेदार है। इसलिए भारत-पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति में तुर्किये का पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर खड़ा होना ज्यादा संभावित है, जबकि सऊदी अरब के लिए सीधे भारत के खिलाफ युद्ध में उतरना आसान नहीं होगा। वह पाकिस्तान को राजनीतिक, आर्थिक या सीमित सैन्य-लॉजिस्टिक मदद दे सकता है, लेकिन मक्का समझौते की मौजूदा सार्वजनिक भाषा से यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान पर हमले की स्थिति में सऊदी और तुर्किये अपने आप भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। यही वजह है कि भारत के लिए असली चिंता इस समझौते की ‘सामूहिक युद्ध’ वाली भाषा से ज्यादा पाकिस्तान को मिलने वाली संभावित अतिरिक्त सैन्य और रणनीतिक ताकत है। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी

पाकिस्तान का विरोधाभास – हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान का सबसे बड़ा विरोधाभास भी सबसे सामने आया है। जिस देश की अपनी सीमाओं पर लगातार तनाव है, जिसे अफगानिस्तान सीमा पर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बलूचिस्तान प्रांत ने आजादी का ऐलान कर दिया है, जिसके अवैध कब्जे वाले पीओके में विद्रोह और दमन तेज होता जा रहा है, वह देश अब मुस्लिम दुनिया की सामूहिक सुरक्षा का प्रहरी बनने की भूमिका तलाश रहा है।

हिमालयी नदियों में बढ़ रहा खतरा, बदलते जलवायु संकट से पहाड़ से मैदान तक मंडरा रही बाढ़ की आशंका

(जयप्रकाश त्रिपाठी)

वैज्ञानिक लगातार आगाह कर रहे हैं कि वर्ष 2030 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ जाएगा। मौसम विज्ञानियों का विश्लेषण बताता है कि वैश्विक तापमान बढ़ने की गति तेज हो रही है और अत्यधिक गर्मी की आवृत्ति भी बढ़ रही है। जलवायु आपदा के कारण हिमालयी नदियां खतरनाक रूप से अपने प्रवाह के रास्ते बदल रही हैं। यह खतरे की घंटी है। उधर, आर्कटिक क्षेत्र, पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इस क्षेत्र में जमे हुए पानी की मात्रा में गिरावट जारी रहना और बैरेंट्स सागर, बेरिंग सागर तथा ओखोत्स्क सागर में जमे हुए जल की क्षति गंभीर बदलाव का संकेत है। इससे सूर्य की रोशनी को परिवर्तित करने की आर्कटिक क्षेत्र की क्षमता में कमी आती है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र, मौसमी रझान और ध्रुवीय क्षेत्रों में आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। ‘चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियोसाइंसेज और सिसुआन यूनिवर्सिटी’ के वैज्ञानिकों के मुताबिक वैश्विक ताप के कारण होने वाले मौसमी बदलावों से ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में नदियां और उनके किनारे बसे इलाकों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता इत्यादि नदियों से लगभग 19 नदियां सीधे जुड़ी हैं, जिनके तेज प्रवाह से जन-धन का व्यापक नुकसान हो सकता है। पहले के मुकाबले दोगुनी तेज गति से ये नदियां, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे तबाह कर सकती हैं। हिमालयी नदियों के 1582 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में तापमान की संवेदनशीलता वैश्विक औसत से लगभग आठ गुना ज्यादा है। नदियों की ही तरह इन क्षेत्रों का तापमान भी दोगुनी गति से बढ़ रहा है। नदियों की गति में बदलाव का सीधा संबंध जलवायु आपदा, तापमान और हिमनदों की हलचल से है।

जलवायु आपदा से अर्थव्यवस्थाएं तहस-नहस हो रही हैं। इसी कारण पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे बदलाव आ सकते हैं, जिन्हें पलटना असंभव होगा। शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंच सकता है। वैज्ञानिक लगातार आगाह कर रहे हैं कि वर्ष 2030 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ जाएगा। मौसम विज्ञानियों का विश्लेषण बताता है कि वैश्विक तापमान बढ़ने की गति तेज हो रही है और अत्यधिक गर्मी की आवृत्ति भी बढ़ रही है। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अंतर्गत तापमान वृद्धि की सीमा अहम है। ऐसी स्थिति में चरम मौसमी घटनाओं, खाद्य असुरक्षा, विस्थापन और पारिस्थितिकी तंत्र ढहने का जोखिम बढ़ेगा। गर्म हो रही जलवायु से वैश्विक वर्षा रझानों में भी बदलाव नजर आ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि दुनिया भीषण गर्मी की ओर बढ़ रही है। यह लगभग तय है कि अगले पांच

हिमालय के आर-पार इस आपदा से बहुत बड़ी आबादी गंभीर रूप से प्रभावित होने का अंदेश है। ताजा अध्ययन के मुताबिक खास तौर से अरुणचल प्रदेश की नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यह भयावह हो सकता है। असम पहले से ही ऐसी आपदाएं झेल रहा है।

जलवायु आपदा से अर्थव्यवस्थाएं तहस-नहस हो रही हैं। इसी कारण पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे बदलाव आ सकते हैं, जिन्हें पलटना असंभव होगा। शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंच सकता है। वैज्ञानिक लगातार आगाह कर रहे हैं कि वर्ष 2030 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ जाएगा। मौसम विज्ञानियों का विश्लेषण बताता है कि वैश्विक तापमान बढ़ने की गति तेज हो रही है और अत्यधिक गर्मी की आवृत्ति भी बढ़ रही है। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अंतर्गत तापमान वृद्धि की सीमा अहम है। ऐसी स्थिति में चरम मौसमी घटनाओं, खाद्य असुरक्षा, विस्थापन और पारिस्थितिकी तंत्र ढहने का जोखिम बढ़ेगा। गर्म हो रही जलवायु से वैश्विक वर्षा रझानों में भी बदलाव नजर आ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि दुनिया भीषण गर्मी की ओर बढ़ रही है। यह लगभग तय है कि अगले पांच

वर्षों के दौरान वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर या फिर उसके आसपास बना रहेगा। ब्रिटेन के मौसम विज्ञान विभाग ने इस रिपोर्ट में पिछले पांच वर्षों की जलवायु का आकलन और अगले पांच वर्षों में तापमान, बारिश और बर्फबारी के रझानों का अनुमान रेखांकित किया है। वर्ष 2026 से 2030 के दौरान, इस बात की लगभग 86 फीसद आशंका है कि कम से कम एक वर्ष, रिकॉर्ड स्तर पर सर्वाधिक गर्म वर्ष होने का मामला सामने आए। अगले पांच वर्ष की अवधि में, कम से कम एक वर्ष के दौरान औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।

बीती जुलाई में, हिमालयी क्षेत्रों से लेकर अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ग्रामीण इलाकों तक आई भीषण बाढ़ की घटनाओं में कई लोग जान गंवा चुके हैं। इस बीच, समय-पूर्व चेतावनी प्रणालियों की गंभीर खामियां भी उजागर हुई हैं। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि इस विनाश के पीछे तेजी से हो रहा शहरीकरण, भूमि उपयोग में बदलाव और जलवायु परिवर्तन जैसी वजहें हैं, जिनसे वातावरण में नमी बढ़ रही है और बाढ़ का खतरा भी लगातार गहराता जा रहा है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अतिरिक्त एक डिग्री

सेल्सियस तापमान बढ़ने पर, वायुमंडल लगभग सात फीसद अधिक जलवाष्प अपने भीतर संचित कर सकता है। इस स्थिति से अत्यधिक वर्षा का जोखिम बढ़ रहा है। साथ ही गर्म होती जलवायु के कारण तेजी से पिघलती बर्फ से हिमनद से जुड़ी बाढ़ का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। अकेले बीती जुलाई में ही दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक के बाद एक, बाढ़ की घटनाएं देखी गईं, जहां कुछ इलाकों में वर्षा 115 मिलीमीटर प्रति घंटे से भी अधिक पहुंच गई। इस आपदा में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 13 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा।

वर्ष 2020 में, दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों में भीषण बाढ़ की घटनाओं में साढ़े छह हजार से अधिक लोगों की मौत हुई थी और लगभग 105 अरब डॉलर की आर्थिक क्षति दर्ज की गई थी। दो साल बाद 2022 में पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से 3.3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इस साल भी यह सिलसिला थमा नहीं है। दक्षिण कोरिया में 16 से 20 जुलाई के बीच रिकॉर्डतोड़ बारिश दर्ज की गई, जहां कुछ इलाकों में वर्षा 115 मिलीमीटर प्रति घंटे से भी अधिक पहुंच गई। इस आपदा में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 13 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा।

बीती जुलाई में अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने टेक्सास के पहाड़ी क्षेत्र में तबाही मचा दी, जिसमें सौ से अधिक लोगों की जान चली गई और अनेक लोग लापता हो गए। इसी तरह नेपाल के रसुवा जिले में हिमनद की सतह पर बनी झील के फटने से अचानक आई बाढ़ में कुछ जलविद्युत संयंत्र और एक पुल सहित कई सड़कें बह गईं। इस भीषण घटना में कम से कम 11 लोगों की जान गई। अनेक लोग अब भी लापता हैं।

वैज्ञानिकों का कहना है कि हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में बाढ़ अब पहले की तुलना में अधिक बार आ रही है, जबकि दो दशक पहले ऐसी बाढ़ आम तौर पर हर पांच से दस साल में एक बार आती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में बाढ़ की ऐसी घटनाओं का खतरा तीन गुना तक बढ़ सकता है। एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि 1.81 अरब लोग यानी दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी विनाशकारी बाढ़ की जद में है। इस आबादी में से 89 फीसद लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों के हैं।

भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने तबाही मचाई है। पुंछ और राजौरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई लोग अब भी लापता हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से जन-जीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। गंगालैंड में बारिश के बाद भूस्खलन से स्कूल की इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से लगभग कई सड़कें बंद हैं। हिमाचल में भी इन दिनों 36 सड़कें बंद हैं। असम के बारह जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।

ठाणे और विशाखापतनम में डेटा सेंटर के निर्माण का विरोध, पानी और बिजली के दोहन का लगाया आरोप



मुंबई, एजेंसी। एआई के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को अब स्थानीय स्तर पर कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तम में निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने गुगल-अदानी और अमेजन द्वारा समर्थित विशाल डेटा सेंटर परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रिहायशी इलाकों में बन रहे ये डेटा सेंटर स्थानीय जल स्रोतों, बिजली आपूर्ति और भूमि पर अत्यधिक दबाव डालेंगे, जबकि कंपनियां उन्नत कूलिंग तकनीकों का हवाला दे रही हैं।

अमेजन और गुगल ने रखा अपना पक्ष: हालांकि, बढ़ते जनाक्रोश के बीच अमेजन और गुगल ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि वे उन्नत एयर-कूलिंग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और स्थानीय पीने के पानी या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सख्त मानकों का पालन करेंगे। गौरतलब है कि यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है, जब केंद्र सरकार डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। इसी साल फरवरी में हुए एआई इम्पैक्ट समिट में पीएम मोदी ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों से अपने डेटा को भारत में ही रखने का आग्रह किया और देश को एआई बुनियादी ढांचे के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। भारत में डेटा केंद्रों को 2022 में बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया, जबकि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में योग्य विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए 2047 तक कर छूट की घोषणा की गई। कई राज्यों ने भी निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियां और प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं।

क्यों हो रहा विरोध: ठाणे में बन रहा डेटा सेंटर बल्कूम और माजिवाड़ा में लगभग 53-58 एकड़ में फैली हुई है। विरोध प्रदर्शन के अभियान का नेतृत्व कर रही साधना प्रधान ने कहा कि ठाणे की आधी आबादी टैंकर के पानी पर निर्भर है। रिहायशी इलाके में डेटा सेंटर क्यों बनाया जा रहा है और सभी नागरिकों को परेशानी में क्यों डाला जा रहा है निवासियों का कहना है कि वे तकनीक या एआई के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में देश के सबसे बड़े डेटा सेंटरों में से एक का निर्माण करने के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे आबादी पर पड़ने वाले प्रभाव पर पूरी तरह विचार नहीं किया गया। निवासियों ने इसका विरोध तब शुरू किया, जब उन्हें पता चला कि डेटा केंद्रों को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखा गया है, जिससे उन्हें चिंता हुई कि पानी और बिजली की कमी के दौरान उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति मिल सकती है।

अमेज़नका आया जवाब

इस विरोध के बाद अमेजन का जवाब आया है, उसने कहा कि ठाणे में बन रहे उसके डेटा सेंटर में कूलिंग के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हम वर्तमान में भारत में अपने किसी भी डेटा सेंटर में कूलिंग के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और न ही कूलिंग के लिए स्थानीय पीने योग्य पानी का उपयोग करते हैं। ठाणे डेटा सेंटर के लिए स्वीकृत जल आपूर्ति परमिट 0.01 एमएलडी है और यह पूरी तरह से बुनियादी मानवीय जरूरतों के लिए है, जिसमें अमेजन कर्मचारियों के लिए शौचालय और पीने का पानी शामिल है। गीगावाट वलस्टर के रूप में नियोजित यह विशाल परियोजना तीन अलग-अलग स्थानों पर विभाजित होगी। यह परियोजना तारलुवाडा में लगभग 200 एकड़, अदावीवरम-मुदसारलोवा में 120 एकड़ और अनाकापल्ली जिले के रामबिल्ली में 160 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी।

जर्मनी में भारतीय छात्र गिरफ्तार, अमेरिका के एरिजोना में प्रेमिका की हत्या का आरोप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के एरिजोना में अपनी प्रेमिका की हत्या के आरोपी भारतीय छात्र को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस



के मुताबिक, आरोपी हत्या के बाद अमेरिका से भारत भागने की कोशिश कर रहा था। वह जर्मनी पहुंचा, लेकिन वहां से आगे की उड़ान लेने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 20 वर्षीय वरुण बाँसिंगरी एरिजोना विश्वविद्यालय में बिजनेस एनालिटिक्स का छात्र था। उस पर 19 वर्षीय जुलिसा रूबी सालाजार की हत्या का आरोप है। पुलिस के अनुसार, 6 अगस्त को टक्सन स्थित एक अपार्टमेंट में सालाजार की हत्या की गई थी।हत्या के बाद भारत भागने की कोशिशटक्सन पुलिस विभाग के

यात्रा नहीं कर सका।गलॉफ्रेंड बनकर मां को भेजे मैसेजजांच में पुलिस को पता चला कि हत्या के बाद आरोपी ने कथित तौर पर सालाजार का मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड अपने पास रख लिए थे। इसके बाद उसने सालाजार की मां को कई मैसेज भेजे। पुलिस का आरोप है कि उसने सालाजार बनकर ये संदेश भेजे, ताकि परिवार को लगे कि वह जीवित है और हत्या की जानकारी छिपाई जा सके। इन संदेशों से सालाजार के परिवार को संदेह हुआ। परिवार की चिंता के बाद पुलिस ने उसके अपार्टमेंट में जाकर हालचाल जानने के लिए जांच की। वहां अधिकारियों को सालाजार का शव मिला।गर्दन पर मिले गला दबाने के निशानस्थानीय मीडिया के अनुसार, 6 अगस्त की शाम

करीब चार बजे टक्सन फायर डिपार्टमेंट को अपार्टमेंट में कार्डियक अरेस्ट की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची टीम ने सालाजार को फर्श पर मृत पाया। उसके शरीर पर एक कंबल गर्दन तक खींचा हुआ था। फायर विभाग के कर्मचारियों ने उसके गले पर गला दबाने के निशान और खरोंचे देखे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की हत्या के रूप में जांच शुरू की।पहले भी हिंसक व्यवहार के आरोपगिरफ्तारी वारंट में आरोपी के खिलाफ पहले के हिंसक व्यवहार से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख है। जांचकर्ताओं के मुताबिक, बाँसिंगरी के खिलाफ पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना पुलिस विभाग ने एक मारपीट के मामले की जांच की थी।

काश पटेल अक्टूबर में जाएंगे रूस क्या एफबीआई प्रमुख कोई बड़ा लेन-देन करने जा रहे

वॉशिंगटन, एजेंसी। एफबीआई निदेशक काश पटेल अक्टूबर के मध्य में रूस की यात्रा करने की तैयारी में हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पटेल 14 और 15 अक्टूबर को मॉस्को के सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे। यह यात्रा ऐसे समय प्रस्तावित है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बना हुआ है। अमेरिकी खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख का रूस जाना इसलिए भी असामान्य माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध लंबे समय से बेहद संवेदनशील दौरे से गुजर रहे हैं। यात्रा की आधिकारिक एजेंडा संबंधी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि पटेल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या क्रेमलिन के किसी वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात करेंगे या नहीं।रूस में पटेल की मेजबानी कौन करेगापटेल की यात्रा के दौरान रूस की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के



मेजबानी करने की संभावना बताई गई है। एफएसबी रूस की प्रमुख सुरक्षा संरचना है, जिसे सोवियत दौरे की केजीबी का उत्तराधिकारी माना जाता है। हालांकि, अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि पटेल एफएसबी के अधिकारियों के अलावा किन लोगों से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे का आधिकारिक एजेंडा भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों से जुड़ी जानकारी में 14-15 अक्टूबर की तारीख और मॉस्को के

बाद सेंट पीटर्सबर्ग जाने की योजना की पुष्टि की गई है। ऐसे में यात्रा के सुरक्षा, खुफिया सहयोग और दोनों देशों के बीच संवेदनशील मुद्दों से जुड़े होने की संभावना पर नजर रहेगी।रूस से 'लेन-देन' की बात क्यों उठीपटेल की संभावित यात्रा पर रूस के एक राज्य समर्थित प्रकाशन ने सवाल उठाया कि अगर एफबीआई निदेशक रूस से किसी तरह की मदद चाहते हैं तो अमेरिका की तरफ से बदले में क्या पेशकश हो सकती है। रूसी एकडेमी ऑफ साइंसेज के आर्बातोव इंस्टीट्यूट से जुड़े व्लादिमीर वासिलिएव ने कहा कि रूस के पास अमेरिकी डेमोक्रेट्स से जुड़ी कथित जानकारी हो सकती है और उसे किसी रूप में अमेरिका के साथ साझा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस बदले में पूछ सकता है कि उसे क्या मिलेगा। हालांकि, यह टिप्पणी किसी आधिकारिक रूसी प्रस्ताव के तौर पर

सामने नहीं आई है। यह केवल संभावित यात्रा को लेकर रूसी पक्ष से की गई अटकल और विश्लेषण है।काश पटेल का रूस से जुड़ा पुराना संदर्भ क्या हैकाश पटेल का नाम पहले भी रूस से जुड़े अमेरिकी राजनीतिक विवादों में सामने आता रहा है।ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान पटेल उन घटनाक्रमों से जुड़े रहे।इनमें 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के अभियान और रूस के कथित संबंधों की जांच पर सवाल उठाए गए थे।पटेल ने इन जांचों को लेकर ट्रंप के पक्ष में रुख अपनाया था।एफबीआई निदेशक बनने के बाद उनकी विदेश यात्राओं को भी अमेरिकी कांग्रेस में करीब से देखा गया है।रूस की प्रस्तावित यात्रा इसी वजह से और ज्यादा संवेदनशील मानी जा रही है।खास बात यह है कि अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर गंभीर मतभेद बने हुए हैं।एफबीआई प्रमुख का रूस दौरा पहले

कब हुआ था और अब क्या सवाल हैंआधिकारिक तौर पर रूस जाने वाले अंतिम ज्ञात एफबीआई निदेशक रॉबर्ट म्यूलर थे, जिन्होंने 2013 में रूस की यात्रा की थी। बाद में म्यूलर को विशेष कबाली नियुक्त किया गया था और उन्होंने 2016 के ट्रंप राष्ट्रपति अभियान और रूस के कथित संबंधों के साथ अमेरिकी चुनाव में रूस के हस्तक्षेप से जुड़े आरोपों की जांच की थी। अब काश पटेल की प्रस्तावित यात्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह यात्रा सिर्फ सुरक्षा और खुफिया संपर्क तक सीमित रहेगी या यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-रूस संबंधों पर भी बातचीत होगी। क्या पुतिन या वरिष्ठ रूसी अधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस और अमेरिका से जिस संभावित 'लेन-देन' की बात कही गई है, क्या उसका कोई वास्तविक आधार है या यह सिर्फ राजनीतिक।

सरकारी कार्यक्रमों में तमिल एंथम अनिवार्य, तमिलनाडु विधान सभा में प्रस्ताव पेश; डीएमके-एआईडीएमके ने किया समर्थन

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के तहत राज्य भर में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में राज्य गीत तमिल थाई वाजथु गाना अनिवार्य कर दिया गया है। विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए विजय ने कहा कि उनकी तमिलगा वेट्टे कडगम (टीवीके) सरकार तमिलनाडु के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने विधायकों से इस कदम का समर्थन करने के लिए राजनीतिक मतभेदों को भुलाने की अपील की।

'मां की तरह पवित्र है हमारी मातृभाषा': विजय ने भावुक भाषण में कहा, 'हमारी मातृभाषा उतनी ही पवित्र है जितनी हमारी मां।' उन्होंने आगे कहा, 'तमिल सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हमारा जीवन और हमारी भावनाएं भी है। तमिल का मतलब है गर्व, तमिल का मतलब है शक्ति।' उन्होंने कहा, 'जिस पल आप तमिल कहते हैं, पूरा तमिलनाडु एकजुट होकर एक साथ खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु में तमिल थाई वाजथु को पहला स्थान मिलना



चाहिए।

तमिल थाई वाजथु को पहला स्थान देना हमारा राज्य का अधिकार है।' तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सभी पार्टियों के सदस्यों से प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा, 'तमिल थाई वाजथु को सबसे पहले गाया जाना चाहिए, इस बात को लेकर कोई राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए। '

डीएमके और एआईएडीएमके ने भी किया समर्थन: इस प्रस्ताव के तहत, तमिलनाडु में शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सबसे पहले तमिल थाई वाजथु गाया जाएगा। इस प्रस्ताव को डीएमके और एआईएडीएमके दोनों दलों के विधायकों का समर्थन मिला। सदस्यों ने सरकारी कार्यक्रमों में राज्य गीत गाना अनिवार्य करने के सरकार के कदम का समर्थन किया। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय की हालिया सलाह के बीच उठाया गया है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम् बजाने के

हाईवे पर मिला खून से लथपथ शव, पुलिस को पत्नी और बेटे पर हत्या का शक



अमरावती, एजेंसी। आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या जिले में पिलरु कस्बे के पास तिरुपति हाईवे एक युवक का खून से लथपथ शव मिला है। युवक की पहचान 47 वर्षीय सुब्रह्मण्यम के रूप में हुई है। शुरुआती तौर पर इसे सड़क दुर्घटना माना जा रहा था। लेकिन मृतक के पिता के आरोपों, घर में मिले खून के धब्बों और फूटेज ने मामले का रुख बदल दिया। पुलिस को संदेह है कि पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों के चलते सुब्रह्मण्यम की घर पर ही हत्या की गई और फिर शव को हाईवे पर फेंककर दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी उमादेवी और बेटे लोहित को हिरासत में ले

परिवहन के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं।

पुलिस ने शुरु की जांच

पिलेरु डीएसपी कृष्णा मोहन ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते थे। युवक के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि उमादेवी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाहतर संबंध था और पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है।

क्या पत्नी का अवैध

संबंध बना हत्या का

मकसद

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या अवैध संबंध हत्या का मकसद बन सकता था और क्या किसी अन्य व्यक्ति ने शव को ले जाने और ठिकाने लगाने में सहायता की थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या शव को जानबूझकर हाईवे पर रखा गया था ताकि मौत को सड़क दुर्घटना जैसा दिखाया जा सके।

19 दिन जेल में बिताए, फिर चोरी कर ली पुलिस स्टेशन से कुर्सी बेंगलुरु में जापानी छात्र ने क्यों किया ऐसा काम

बेंगलुरु, एजेंसी। 2019 में अंग्रेजी सीखने और भारत घूमने बेंगलुरु आए जापानी छात्र हिरोतोशी तनाका की लाइफ एक विवाद के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। यहां एक कोचिंग सेंटर प्रमुख के साथ हुए झगड़े के बाद आरटी नगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 19 दिनों तक अवैध रूप से जेल में रखा। दरअसल, जापानी छात्र तनाका बेंगलुरु पहुंचकर एक निजी अंग्रेजी अकादमी में दाखिला लिया। वह अकादमी से असंतुष्ट था क्योंकि आरोप था कि कक्षाएं बार-बार रद्द की जा रही थीं और अनियमित रूप से संचालित हो रही थीं। उसने कहा कि अकादमी प्रमुख से स्पष्टीकरण मांगने के बार-बार प्रयास अनुत्तरित रहे, जिससे तनाव बढ़ता गया। यह विवाद अंततः बहस में बदल गया। उसने आरोप लगाया कि उसे उकसाया गया, जिसके कारण उसे गुस्सा आ गया और उन्होंने अकादमी प्रमुख को घूंसा मार दिया। झगड़े के बाद, आरटी नगर पुलिस ने उसके खिलाफ जानबूझकर चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया। हालांकि, यह अपराध जमानती था, फिर भी तनाका को 23 नवंबर, 2019 को गिरफ्तार कर बेंगलुरु केंद्रीय जेल भेज दिया गया। उसे 11 दिसंबर को रिहा किए जाने से पहले 19 दिन जेल में बिताने पड़े।

7 साल बाद मुकदमा जितने में कामयाब: कानूनी व्यवस्था ने समझ पाने, भाषा की दिक्कत और गंभीर मेडिकल स्थिति (दृष्टादृ) के बावजूद वह पुलिस के खिलाफ मुकदमा जीतने में कामयाब रहा। 7 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, कर्नाटक सरकार ने अवैध हिरासत के लिए जापानी छात्र



तनाका को 75,000 रुपये का मुआवजा दिया है। क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने माना था कि उन्हें 19 दिनों तक अनावश्यक रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया था।

गिरफ्तार होने के लिए चुआई एसपी ऑफिस की कुर्सी: इस लंबी कानूनी लड़ाई का सबसे अजीबोगरीब मोड़ 28 फरवरी 2021 की सुबह आया, जब आर्थिक तंगी से जूझ रहे और देश छोड़ने का आदेश झेल रहा तनाका आरटी नगर स्थित जेसी नगर एसपीो दफ्तर में घुसा और वहां से एक सफेद प्लास्टिक की कुर्सी उठाई, उसके साथ सेल्फी ली और उसे बीटीएम लेआउट स्थित अपने घर ले आए। दरअसल, हिरोतोशी तनाका का इरादा चोरी करना नहीं था, बल्कि वह चाहते थे कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, ताकि इस गिरफ्तारी के बखाने वे भारत में रहकर मानवाधिकार आयोग में दर्ज अपनी शिकायत को कानूनी लड़ाई जारी रख सकें। हिरोतोशी तनाका का उद्देश्य उस 'भ्रष्ट' पुलिसकर्म की पर्दाफास करना था, जिसने उसे फजी केस में फंसाया था। हालांकि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने केस खारिज कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने 28 फरवरी तक भारत छोड़ने का आदेश दिया।

केरलम के गृहमंत्री को खुली चुनौती देने वाला हिस्ट्रीशीटर अर्जुन अयांकी गिरफ्तार



कन्नूर, एजेंसी। केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्नियला को इंटरनेट मीडिया के जरिये खुली चुनौती देने और पुलिस अधिकारियों को धमकाने के आरोपी हिस्ट्रीशीटर बदमाश अर्जुन अयांकी को रविवार को कन्नूर से गिरफ्तार कर लिया गया। हिस्ट्रीशीटर वह अपराधी होता है जिसका लंबा आपराधिक रिकार्ड होता है तथा जिसका नाम पुलिस थाने के 'हिस्ट्री शीट' (अपराध इतिहास रजिस्टर) में दर्ज होता है। कन्नूर सिटी पुलिस आयुक्त बीबी. विजय भारत रेड्डी ने बताया कि अर्जुन को गिरफ्तार करने ने के लिए पुलिस ने देर रात तक अभियान चलाया। शनिवार सुबह से ही उसकी तलाश की जा रही थी। सूत्रों के अनुसार अर्जुन को रात करीब 2.30 बजे एक वकील के अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया। अर्जुन के खिलाफ 23 मामले दर्ज हैं। हाल ही में उस पर गृह मंत्री चेन्नियला को चुनौती देने और इंटरनेट मीडिया पर मुख्यमंत्री वीडी. सतीशन को बदनाम करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

तेलंगाना में 54 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त, चार

गिरफ्तार; नागपुर ले जाई जा रही थी छेप

हैदराबाद, एजेंसी। तेलंगाना के यदाद्री भुवनागिरी जिले में एक प्रतिबंधित नशीली पदार्थ मेफेड्रोन की तस्करी में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए 27 किलोग्राम अवैध पदार्थ की कीमत 54 करोड़ रुपये है। पुलिस ने बताया कि यह अवैध पदार्थ वितरण के लिए महाराष्ट्र के नागपुर ले जाया जा रहा था। बिबीनगर पुलिस थाने की एक टीम ने 8 अगस्त को कोंडामडुगु गांव के बाहरी इलाके में एक विशेष आपरेशन चलाया और एक कार को रोका। यदाद्री भुवनागिरी के पुलिस अधीक्षक अक्षाश यादव ने कहा कि तलाशी के दौरान पुलिस ने 27 किलोग्राम मेफेड्रोन और दो प्लास्टिक के बैग में नशीले पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला रासायनिक पदार्थ 40 किलोग्राम एसोडोन बरामद किया।

संक्षिप्त

समाचार

मध्यप्रदेश पुलिस की संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति, वैज्ञानिक विवेचना, आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग एवं सतत मॉनिटरिंग के सकारात्मक परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में गुना पुलिस ने थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम चक चुरेला में हुई चोरी का मात्र 06 दिनों में सफल खुलासा करते हुए सभी आरोपियों की पहचान सुनिश्चित कर ली है। प्रकरण में 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 1 करोड़ 47 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। यह सफलता पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत सिंह सुमन, एसडीओपी गुना श्री विवेक अछाना तथा पुलिस टीमों के सुनियोजित रणनीति, उत्कृष्ट समन्वय और निरंतर फील्ड ऑपरेशन के माध्यम से प्राप्त हुई है। दिनांक 02-03 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि ग्राम चक चुरेला निवासी श्री बाबूलाल मोना के घर से अज्ञात बदमाश तिजोरी और मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए थे। तिजोरी में लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम सोने के आभूषण, लगभग 3 किलोग्राम चांदी के जेवर, 11 लाख 50 हजार रुपये नकद रखे थे। घटना के बाद थाना फतेहगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विशेष जांच प्रारंभ की गई। घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध नहीं होने के बावजूद पुलिस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी जांच पद्धति अपनाते हुए फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों, डॉंग स्वाइड, तकनीकी साक्ष्यों के सूक्ष्म विश्लेषण, मजबूत मुखबिर तंत्र, निरंतर फील्ड ऑपरेशन, गहन पूछताछ तथा विभिन्न स्तरों पर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर सभी आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की। पुलिस ने मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न जिलों में लगातार समन्वित अभियान चलाकर 08 अगस्त को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने सोने के आभूषण, जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 48 लाख रुपये है, बरामद किए हैं। प्रकरण के शेष आरोपियों की गिरफ्तारी एवं शेष चोरी गई संपत्ति की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। मध्यप्रदेश पुलिस आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रभावी खुफिया तंत्र और समन्वित टीमवर्क के आधार पर अपराधियों के विरुद्ध लगातार निर्णायक कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण तथा आमजन की सुरक्षा एवं विश्वास बनाए रखना मध्यप्रदेश पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित वैधानिक कार्रवाई भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगी। यह कार्रवाई पुनः सिद्ध करती है कि सुदृढ़ नेतृत्व, वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विश्लेषण, मजबूत मुखबिर तंत्र तथा समन्वित पुलिसिंग के माध्यम से चुनौतीपूर्ण अपराधों का भी त्वरित एवं सफल अनावरण संभव है।

मंत्री परमार के निर्देश पर प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश का अंतिम अवसर

भोपाल । उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार के निर्देश पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश का एक और अंतिम अवसर दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग चरण आयोजित किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 10 से 14 अगस्त 2026 तक संचालित होगी।

रिक्त सीटों पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर मिलेगा प्रवेश: अतिरिक्त छष्ट चरण में प्रवेश केवल उपलब्ध रिक्त सीटों पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिया जाएगा। रिक्त सीटों की जानकारी विद्यार्थी के लॉगिन के साथ-साथ संबंधित महाविद्यालय के लॉगिन पर भी प्रदर्शित होगी। पंजीकृत विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय में सीधे पहुंचकर प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

विद्यार्थी जिस महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, वहां सीट उपलब्ध होने की स्थिति में सीधे महाविद्यालय पहुंचकर प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी अथवा किसी समस्या के समाधान के लिए संबंधित महाविद्यालय के हेल्प सेंटर से संपर्क किया जा सकेगा।अतिरिक्त छष्ट चरण में नवीन पंजीकृत विद्यार्थी केवल एक महाविद्यालय में पंजीयन कर सकेंगे। संबंधित महाविद्यालय के हेल्प सेंटर पर आवश्यक वेरिफिकेशन के उपरांत विद्यार्थी उसी दिन प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। अतिरिक्त छष्ट प्रक्रिया 14 अगस्त को शाम 5 बजे तक संचालित होगी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त किया जा सकेगा। 14 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद प्राप्त प्रवेश मान्य नहीं होंगे। संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी।

आम जनता की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए सदैव तत्पर रहें अधिकारी-कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि : परमार

भोपाल । उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री तथा पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान, शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियाव्ययन तथा जवाबदेह एवं जवाह्तिषी प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। अधिकारी-कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि आमजन की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए सदैव तत्पर रहें और जनता के बीच निरंतर संवाद एवं जुड़ाव बनाए रखें।

प्रभारी मंत्री श्री परमार ने शनिवार को पन्ना कलेक्टर कार्यालय सभागार में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान एवं हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी 8 जनवरी तक प्रत्येक शुक्रवार को विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी क्षेत्र भ्रमण कर आमजन की समस्याओं को सुनेंगे और उनके निराकरण के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

संस्कार सुधा फाउंडेशन का आयोजन सतरंगी सावन 15 एवं 16 अगस्त को

स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी एवं अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

भोपाल। नगर संवाददाता

सामाजिक संस्था संस्कार सुधा फाउंडेशन प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सतरंगी सावन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 15 एवं 16 अगस्त 2026 को भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित तुलसी मानस प्रतिष्ठान (मानस भवन) में किया जा रहा है। संस्कार सुधा फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. रश्मि अग्रवाल (सोनू दीदी) ने बताया कि कार्यक्रम में संस्था द्वारा स्व सहायता समूह तथा गृह उद्योग से जुड़ी बहनों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जिससे उनके द्वारा तैयार घरेलू उत्पादों के प्रचार-प्रसार के साथ ही विक्रय किया जा सकेगा। इसके साथ ही सतरंगी सावन में मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से महिलाओं द्वारा



आकर्षक वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। अध्यक्ष डॉ. रश्मि अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम के प्रथम दिन 15 अगस्त को देशभक्ति पर आधारित नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन तथा 16 अगस्त को गृहणी महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार से सुसज्जित पारंपरिक वेशभूषा में तीज क्रीन, फैशन शो एवं सतरंगी सावन के मंच पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं समाजसेवियों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सतरंगी सावन कार्यक्रम में शहर की अनेक विभूतियों के साथ ही लगभग 1500 से अधिक अतिथियों के शामिल होने की उम्मीद है। आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने का अनुरोध है।

भोपाल के आसपास बदलेगी इंडस्ट्री की तस्वीर, 88 पार्क तैयार, 51 नए क्षेत्र बनेंगे, तीन मेगा हब देंगे 11 हजार युवाओं को रोजगार

भोपाल, नप्र। राजधानी भोपाल का औद्योगिक दायरा अब सिर्फ बीएचईएल या मंडीदीप तक सीमित नहीं रह गया है। भोपाल सहित रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और नर्मदापुरम के 50 किलोमीटर के दायरे में उद्योगों का एक विशाल जाल बिछ रहा है।

इस बेल्ट में वर्तमान में 88 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित हो चुके हैं और 51 नए औद्योगिक क्षेत्र आकार ले रहे हैं। खास बात यह है कि अब केवल भारी उद्योगों पर निर्भरता खत्म हो रही है और अलग-अलग सेक्टर के लिए विशेष क्लस्टर तैयार किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों नए रोजगार पैदा होंगे।

सेक्टर आधारित नए क्लस्टरर्स का निर्माण : अब अलग-अलग उद्योगों की पहचान के हिसाब से क्लस्टर बन रहे हैं। जैसे, अचारपुरा को गारमेंट और टेक्सटाइल के लिए, तामोट को प्लास्टिक-पॉलिमर के लिए और बड़ियाखेड़ी-आष्टा को लॉजिस्टिक्स व मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी चंद्रमौली शुक्ला के मुताबिक, प्रदेश में पुरानी इंडस्ट्रीज को रिडेवलप करने के साथ-साथ शहर के भीतर की खाली जमीनों का भी सही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के तहत भोपाल में सतगढ़ी और मोनल के आसपास की खाली जमीनों पर नए इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किए जाएंगे।

इन तीन नए हब से मिलेंगे 11 हजार रोजगार : आने वाले समय में भोपाल के पास तीन नए औद्योगिक हब पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, जो करीब 11,000 युवाओं को रोजगार देंगे:



- **बैरसिया (एगो-फूड प्रोसेसिंग हब) :** 33.61 हेक्टेयर में फैले इस इलाके में एगो-प्रोसेसिंग, लाइट इंजीनियरिंग और फूड पैकेजिंग की इकाइयां लगाई जाएंगी। वर्ष 2026 के अंत तक यहां निर्माण शुरु करने का लक्ष्य है, जिससे 1,500 से 2,000 रोजगार के अवसर बनेंगे।
- **सतगढ़ी (लाइट इंडस्ट्री हब) :** भोपाल की सीमा से लगे इस इलाके में 69.91 हेक्टेयर में ऑटो एंसिलरी, असेंबलिंग यूनिट्स और एमएसएमई (MSME) वलस्टर विकसित किए जा रहे हैं। 2026-27 तक इसके तैयार होने से 3,000 से 4,000 नौकरियां पैदा होंगी।
- **बड़वाई (आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स) :** राजा भोज एयरपोर्ट के पास बनने वाले इस हब में डेटा सेंटर, आईटी स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबलिंग के लिए प्लग एंड प्ले की सुविधा होगी। इससे सबसे ज्यादा 4,000 से 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों का भी होगा विस्तार : पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को आधुनिक रूप दिया जा रहा है, ताकि उत्पादन और निर्यात दोनों बढ़ सकें :

- **मंडीदीप :** यह सबसे बड़ा हब है, जहां 60 हजार से ज्यादा लोग काम करते हैं। यहां 6 मंजिला प्लग एंड प्ले टावर, 96 रेडी-टू-यूज यूनिट्स और 1776 सीटर वर्किंग वुमन होस्टल बनाया जाएगा।
- **अचारपुरा :** गारमेंट सेक्टर वाले इस हब में 6 मंजिला फैक्ट्री ब्लॉक बनेगा और इसका 31.21 हेक्टेयर में विस्तार किया जाएगा।
- **गोविंदपुरा :** इलेक्ट्रिकल और फैब्रिकेशन के इस हब में बंद हो चुकी इकाइयों की जमीन लेकर नए टेक-आधारित स्टार्टअप्स को दी जाएगी।
- **बगरोदा व तामोट :** बगरोदा में 19 हेक्टेयर जमीन पर एगो और फार्मा पैकेजिंग का विस्तार होगा, वहीं तामोट में 41 हेक्टेयर भूमि पर नए प्लास्टिक-पॉलिमर उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
- **बड़ियाखेड़ी व आष्टा :** लॉजिस्टिक्स और ऑटो पार्ट्स के लिए मशहूर बड़ियाखेड़ी में 55.5 हेक्टेयर भूमि का विस्तार होगा, जबकि आष्टा में एक नया मेगा इंडस्ट्रियल वलस्टर बनाया जाएगा।

नई दिल्ली में 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में मप को मिली सराहना

भोपाल, नप्र।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विगत दिनों दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थल तक एयारपोर्ट से मेट्रो रेल से यात्रा की। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमारे लिये गर्व की बात है कि दिल्ली की मेट्रो रेल वर्ष 2018 से मध्यप्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विद्युत से संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो संचालन के लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2044 तक निरंतर विद्युत आपूर्ति की जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये किये जा रहे उल्लेखनीय कार्यों पर जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उस समय बेकग्राउण्ड में स्क्रीन पर दिल्ली मेट्रो में सफर संबंधित चित्र प्रदर्शित हो रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश के कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में कहा कि मध्यप्रदेश वर्ष 2030 तक देश के 500 गीगा वॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य नवकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण तथा हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। म.प्र. आज देश

के अग्रणी राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी-2026 के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी तथा भूतान के ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री एच.ई. ल्योनपो जेम खोरिंग तथा श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री श्री अनुरा करुणायिलका, अपर मुख्य सचिव नवकरणीय ऊर्जा मध्यप्रदेश श्री मनु श्रीवास्तव सहित देश-विदेश के ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना ने देश में पहली बार सौर ऊर्जा का टैरिफ कोयला आधारित विद्युत से भी कम स्थापित किया। इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेन्ट्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्राप्त हुआ तथा इसकी केस स्टडी हावर्ड युनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का महानिदेशक दिल्ली मेट्रो श्री प्रमित गर्ग ने दिल्ली मेट्रो को बगैर किसी निवेश के मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिये आभार जताया।

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के 5 प्रमुख स्टेशनों पर 12 से 15 अगस्त तक पार्सल बुकिंग पर प्रतिबंध

भोपाल, नप्र। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली क्षेत्र के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 12 से 15 अगस्त 2026 तक पार्सल बुकिंग एवं हैंडलिंग पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजूरत (निजामुद्दीन, आनंद

विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर लागू रहेगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि उक्त अवधि में इन 5 स्टेशनों पर लीज पर संचालित द्वितीय श्रेणी लगेज रैक डिब्बा, पार्सल वैन एवं डिमांड पार्सल

राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करेंगी तिरंगा यात्रा: उप मुख्यमंत्री

भोपाल। नगर संवाददाता

उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल रीवा नगर निगम क्षेत्र में सिरमौर चौक से गंगा वाटिका तक आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने हेमू कालाणी चौक स्थित महान स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धेय हेमू कालाणी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुए ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी अभियान में लोगों से सहभागिता करने का आह्वान किया।

सभी लोगों से अपने घरों पर भारत के स्वाभिमान के प्रतीक हमारे तिरंगे को फहराने के लिए प्रेरित किया। इस विशाल तिरंगा यात्रा में लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर इसे और भव्य बना दिया। तिरंगा यात्रा देशवासियों में राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करेगी।

तिरंगा हमारी आन-बान और शान प्रतीक है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल, नगर निगम अध्यक्ष श्री व्यंकटेश पाण्डेय, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र



गुप्ता, पूर्व विधायक श्री के. पी. त्रिपाठी, पूर्व महापौर श्री राजेंद्र ताम्रकार, विंध्य विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. अजय सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राम सिंह, श्री कमलेश्वर सिंह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्रीमती मनीषा पाठक सहित बड़ी संख्या गणमान्य नागरिक और आम जन उपस्थित रहे।



भारी बारिश से भोपाल और बैरसिया के बीच सड़क संपर्क टूटा, पुल के ऊपर बह रही हलाली बाणगंगा नदी

भोपाल, नप्र। भोपाल जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से भोपाल शहर और बैरसिया संपर्क टूट गया है, ईंटखेड़ी पर हलाली बाणगंगा नदी पुल के ऊपर बह रही है। इधर भोपाल कलेक्टर के निर्देश पर आज सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रहेगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय भोपाल जिले में अत्यधिक बारिश की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। अवकाश का आदेश सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। इसमें मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपी बीएस), सीबीएसई, आइसीएसई तथा अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूल भी शामिल हैं।

सभी शिक्षक और कर्मचारी स्कूल आएंगे हालांकि विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षकों और विद्यालयीन कर्मचारियों को अवकाश नहीं दिया गया है। आदेश के मुताबिक सभी शिक्षक एवं कर्मचारी विद्यालयीन समय में अपने कार्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य द्वारा 10 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। निचले इलाकों में जलभराव उन्होंने बताया कि बारिश और जलभराव को देखते हुए फैसला लगातार बारिश के बीच विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। खासकर निचले इलाकों में जलभराव और बारिश के दौरान आवगमन में आने वाली परेशानी को देखते हुए स्कूलों में विद्यार्थियों की आवाजही रोकने का फैसला किया गया है।

भोपाल मंडल में 9 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा ‘हर घर तिरंगा’ अभियान–2026

भोपाल, नप्र।

देशभर में आजादी के अमृतकाल के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे ‘हर घर तिरंगा’ अभियान-2026 के तहत भोपाल मंडल में 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

अभियान के दौरान भोपाल मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, रेलवे परिसरों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं महत्वपूर्ण भवनों को यथासंभव तिरंगा रंगों की आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा।

प्रमुख स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की वाद्य धुन का प्रसारण भी किया जाएगा,

जिससे यात्रियों एवं आमजन में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा।

भोपाल मंडल द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ यात्रियों और आम नागरिकों को अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा ‘सेल्फी विद तिरंगा’ अभियान में सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

‘हर घर तिरंगा’ अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान को नमन करते हुए प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को और अधिक सुदृढ़ करना है। भोपाल मंडल इस अभियान में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उक्त स्टेशनों पर पार्सल की लोडिंग अथवा अनलोडिंग के लिए रुकती हैं।

रेल प्रशासन ने यात्रियों एवं पार्सल ग्राहकों से स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने तथा निष्ठाविरत नियमों का पालन करने की अपील की है।





खाना बनाना और सफाई जीवन कौशल हैं, जेंडर रोल नहीं: प्रियंका

बेसिक एडिल्टिंग है घर के काम, प्रियंका चोपड़ा ने रखी अपनी बात एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने घर की जिम्मेदारियों से जुड़ी जेंडर स्टिरियोटाइप (लिंग-आधारित रूढ़िवादी सोच) के खिलाफ बात की और कहा कि खाना पकाने और सफाई जैसे कामों को सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं माना जाना चाहिए। इसके बजाय, उनका मानना है कि ये जिंदगी के जरूरी हुनर हैं जो हर वयस्क (चाहे वह पुरुष हो या महिला) को आने चाहिए। कान्स लॉयंस में एक इंटरव्यू के दौरान, प्रियंका ने उस पुरानी सोच पर बात की जिसके तहत महिलाओं से घर की जिम्मेदारियों संभालने की उम्मीद की जाती है, जबकि पुरुषों को अक्सर इनसे छूट मिल जाती है। इस सोच को चुनौती देते हुए, ग्लोबल स्टार ने साफ किया कि घरेलू कामों को जेंडर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सफाई और खाना पकाना महिलाओं का काम नहीं है। ये बुनियादी तौर पर वयस्क होने के नाते जरूरी काम हैं। आलस को जेंडर से न जोड़ें। मनोरंजन की बदलती दुनिया पर प्रियंका बातचीत के दौरान, प्रियंका ने इस बारे में भी बात की कि कैसे टेक्नोलॉजी ने मनोरंजन इंडस्ट्री को बदल दिया है और फिल्म बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। प्रियंका ने कहा, अगर आप फिल्ममेकिंग में आना चाहते थे, तो आपको यह तय करना होता था कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। इंडस्ट्री में आना वाकई मुश्किल था। उन्होंने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस हकीकत को बदल दिया है, जिससे क्रिएटर्स पारंपरिक इंडस्ट्री स्ट्रक्चर पर निर्भर हुए बिना अपने आइडिया सीधे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। 15 करोड़ उन्होंने आगे कहा, अब, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई आइडिया है, तो उसे शूट करें, और वह ऑब्सेशन जैसी फिल्म बन सकती है जो अभी-अभी रिलीज हुई है। एंटरटेनर होने और एंटरटेनमेंट बिजनेस में होने के लिए यह कितना शानदार समय है। प्रोफेशनल तौर पर, प्रियंका के पास कई प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी है। उन्होंने हाल ही में बताया कि वह एक आने वाले प्रोजेक्ट में एंजेलिना जोली के साथ काम करेंगी। फॉर्च्यून इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में, प्रियंका ने इस सहयोग की पुष्टि की लेकिन कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। यह अभी साफ नहीं है कि यह प्रोजेक्ट कोई फिल्म है, कोई कमर्शियल कैपेन है या कोई चैरिटी से जुड़ा काम है। वह ऑरलैंडो ब्लूम के साथ भी एक नया वेंचर शुरू करने वाली हैं, जबकि एंजेलिना जोली के साथ उनके जुड़ने की खबर ने फैंस के बीच उत्साह पैदा कर दिया है। इस बीच, प्रियंका अगली बार एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म वाराणसी में नजर आएंगी, जिसमें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं। यह प्रोजेक्ट उन फिल्मों में से एक है जिनका बेसव्री से इंतजार किया जा रहा है।



श्रेया कालरा ने ठुकराया Bigg Boss 20 बोलीं बहुत कुछ झेल चुकी

सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। शो के नए सीजन की शुरुआत 6 सितंबर 2026 से होने की बात सामने आई है और इसके साथ ही संभावित कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर हर दिन नए नाम सामने आ रहे हैं। इसी बीच 'लोकअप सीजन 2' की विनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा का नाम भी 'बिग बॉस 20' के संभावित कंटेस्टेंट के तौर पर चर्चा में था। हालांकि, अब श्रेया ने खुद इन खबरों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। श्रेया कालरा ने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक वॉयस नोट साझा किया और 'बिग बॉस 20' में बतौर कंटेस्टेंट शामिल होने की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग उनसे शो में जाने को लेकर सवाल कर रहे हैं, उन्हें फिलहाल यह समझ लेना चाहिए कि वह किसी रियलिटी शो में बतौर प्रतिभागी शामिल होने की तैयारी नहीं कर रही हैं। श्रेया ने अपने बयान में अपनी हालिया मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि फिलहाल 'बिग बॉस 20' उनके लिए सही नहीं है। श्रेया ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर उन्हें शो में किसी अलग भूमिका में शामिल होने का प्रस्ताव मिलता है तो वह उस पर विचार कर सकती हैं। उनके मुताबिक, अगर उन्हें किसी ग्रुप को होस्ट करने, गाइड करने या लीड करने का अवसर दिया जाता है, तो वह इसमें रुचि लेंगी। हालांकि, बतौर कंटेस्टेंट शो में शामिल होने को लेकर उन्होंने साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि प्रतियोगी के तौर पर 'बिग बॉस' जैसे शो का हिस्सा बनना उनके लिए फिलहाल काफी मुश्किल होगा। श्रेया के इस बयान के बाद उनके 'बिग बॉस 20' में शामिल होने की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। इससे पहले सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट सर्किल में उनके नाम को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। उनके फैंस भी यह जानने को उत्सुक थे कि क्या वह सलमान खान के शो में नजर आएंगी। अब श्रेया के खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट करने के बाद उनके फैंस को उनकी ओर से आगे किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा। वहीं 'बिग बॉस 20' के संभावित कंटेस्टेंट्स को लेकर कई अन्य नाम भी चर्चा में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, शो के निर्माताओं ने कुछ चर्चित टीवी कलाकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों से संपर्क किया है। संभावित नामों में अभिनेत्री माही विज, गीता बसरा और जन्नत जुबैर के अलावा कॉमेडियन सुनील पाल और कंटेड क्रिएटर शोविक चक्रवर्ती के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। अंजलि अरोड़ा और उर्फी जावेद जैसे चर्चित नामों की भी शो को लेकर चर्चा हो रही है। अरबाज पटेल, भगीरथ भट्ट, भाव्या सिंह, रुरु ठाकुर, रिंथिमा गुप्ता और तुषार कारवार के नाम भी संभावित कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में बताए जा रहे हैं। हालांकि, इन नामों में से किसी को आधिकारिक तौर पर कंटेस्टेंट घोषित किए जाने तक इन्हें केवल चर्चाएं और संभावित नाम ही माना जाना चाहिए। 'बिग बॉस' का हर सीजन अपने कंटेस्टेंट्स, विवादों, टास्क और घर के अंदर होने वाली गतिविधियों के कारण चर्चा में रहता है। ऐसे में 'बिग बॉस 20' को लेकर भी दर्शकों की दिलचस्पी काफी ज्यादा है। सलमान खान के शो की शुरुआत को लेकर तारीख सामने आने के बाद अब फैंस की नजरें आधिकारिक कंटेस्टेंट लिस्ट और शो के फॉर्मेट पर टिकी हुई हैं।



16 अगस्त तक ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

ओटीटी पर इस हफ्ते एक बाद एक फिल्में और सीरीज रिलीज होगी जिन्हें आपको अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। क्योंकि इनकी कहानी बेहद खास है और आपके दिमाग को एकदम हिला कर रख देगी। हर दिन आपको एक सीरीज या फिल्म ओटीटी पर देखने को मिलेगी। तो इंतजार किस बात का आज यहां हम आपको इन फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं इन्हें अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर लें। मोरिन्हा, द लीजेंड ऑफ किचन सोल्जरसीजन 1, फिफटीज प्रोफेशनल्स सीजन 1 रीवर सीजन 4, द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2, कैटलन, अ चाइल्ड ऑफ माय ऑन, कॉकटेल 2, भारत भाग्य विधाता, डॉट से गुड लक।

जाह्नवी ने डीपनेक गाउन में दिखाया फैशन जलवा

बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसों में से एक हैं जाह्नवी कपूर. जान्हवी कपूर के इंस्टाग्राम पर लाखों फैंस हैं. एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसों में से एक हैं जाह्नवी कपूर. जान्हवी कपूर के इंस्टाग्राम पर लाखों फैंस हैं. एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म %बावल को लेकर चर्चा में हैं. इन दिनों जाह्नवी की ओटीटी रिलीज फिल्म %गुड लक जैरी% हॉटस्टार पर रिलीज हो रही हैं. फिल्म %गुड लक जैरी की शानदार सफलता के बाद भी, जान्हवी कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कुछ चमकदार स्टारडस्ट के साथ, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं. हाल ही में जाह्नवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं. इस फोटोज में जान्हवी काफी खूबसूरत दिख रही हैं. इन फोटोज में जाह्नवी ने गोल्डन रंग का बॉडीकॉन गाउन पहना हुआ है. इस ड्रेस के साथ मिनिमम मेकअप की हुई यह बॉलीवुड एक्ट्रेस हुस्न की बिजलियां गिरा रही हैं. हाल ही में जाह्नवी कॉफी विथ करण में सारा अली खान के साथ शामिल हुई थी. उन्होंने इस दौरान कई बड़े खुलासे करते हुए ऑडियंस को सरप्राइज दिया।



दिल्ली के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग बंद

भोपाल। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी के मद्देनजर रेलवे ने 12 से 15 अगस्त तक दिल्ली के पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग और हैडलिंग पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशनों पर लागू रहेगा। भोपाल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के अनुसार, इस अवधि में इन स्टेशनों से आने-जाने वाले सभी प्रकार के पार्सल यातायात पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें तीज पर संचालित द्वितीय श्रेणी लगेज रैक डिब्बे, पार्सल वैन और डिमांड पार्सल वैन भी शामिल हैं। प्लेटफॉर्म और पार्सल गोदाम रहेंगे सुरक्षा कड़ी रखे जाएंगे। इस दौरान दिल्ली के इन पांच स्टेशनों पर पार्सल की लोडिंग और अनलोडिंग नहीं हो सकेगी। हालांकि यात्रियों को अपना निजी सामान अपनी डिब्बों में सब ले जाने की अनुमति रहेगी। वहीं पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग निर्धारित व्यावसायिक औपचारिकताओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद की जा सकेगी।

चार युवाओं ने बनाई नशे में ड्राइविंग रोकने वाली स्मार्ट डिवाइस

ड्राइवर नशे में होगा तो गाड़ी चलेगी ही नहीं

भोपाल। पहले टेस्ट, फिर स्टार्ट... इसी सोच के साथ इंदौर के चार युवाओं ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है, जो नशे में वाहन चलाने वालों के लिए सख्त दीवार बनकर खड़ी होगी। गाड़ी में फिट होते ही यह डिवाइस ड्राइवर से नशे का टेस्ट मांगेगी। बिना टेस्ट दिए गाड़ी का इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। इंदौर के युवाओं ने इस स्मार्ट तकनीक को सेफइन्नाइट नाम दिया है। नशे में होते हादसों की बढ़ती संख्या देखकर एक दिन सोए कर रहे शहर के ईशान गर्ग ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा हो कि नशा किया व्यक्ति गाड़ी स्टार्ट ही न कर सके। उन्होंने तीन साल पहले इस पर अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर काम किया और अब इस तरह की डिवाइस बनकर तैयार है कि अगर ये किसी गाड़ी में लगा दी जाए तो गाड़ी तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक कि उसे चलाने वाला टेस्ट नहीं दे देगा, भले ही वो नशे में हो या न हो। टेस्ट देने के बाद जब तक सॉफ्टवेयर हां नहीं कर देगा गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। फाउंडर ईशान गर्ग बताते हैं कि यह पूरी तरह से टैपरप्रूफ और बायप्रूफ है। इस डिवाइस के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। एक हार्डवेयर गाड़ी में इंस्टॉल होता है और हम एक सॉफ्टवेयर देते हैं, जो आपस में कनेक्टेड है। दो से तीन सेकंड का एक छोटा सा टेस्ट होता है और इस टेस्ट को पास करने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट होती है। अगर गाड़ी चलाने वाला नशे में पाया जाता है तो गाड़ी का इग्निशन अपने आप लॉक हो जाता है और अलार्म बज जाता है। सबसे खास बात यह है कि डिवाइस गाड़ी चलाने वाले की हर 10 मिनट में फोटो खींचकर सॉफ्टवेयर पर भेजती रहती है, ताकि यह पता चलता रहे कि जिसने टेस्ट दिया है, वही गाड़ी चला रहा है।



ऑन डिमांड टेस्ट ऑप्शन भी

डिवाइस के सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मुख्य एक्सेस इस सॉफ्टवेयर से कभी भी ऑन डिमांड टेस्ट कर सकेगा। डिवाइस पर एक कॉल ऑप्शन जाएगा, जो गाड़ी के चालक को एक्सेस करके उसी वक्त टेस्ट देना होगा।

8 महीने से चल रही थी टेस्टिंग

डिवाइस के तैयार होने ही पिछले 8 महीने से इसका टेस्ट चल रहा था। चारों दोस्त अभी तक भोपाल में कुछ ट्रैवल कंपनी, एक मालिकों, बस मालिकों को इसका डेमो दे चुके हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर के सामने भी इसका डेमो हुआ है। टीम बताती है।

3 साल लगातार किया काम

सेफइन्नाइट पर 25 साल के ईशान गर्ग, उत्कर्ष सिंह, ऋतिक गर्ग और अनिकेत ठुवानों ने 2023 में काम शुरू किया था। 3 साल की मेहनत के बाद अब चारों ने भारत की ऐसी अपनी पहली डिवाइस बना दी है और इसका पेटेंट भी फाइल कर दिया है। उनका उद्देश्य यह था कि सफर सुरक्षित हो।

जीएसटी रिवीजन के आदेश की होगी समीक्षा

प्रदेश में पहली बार एक नई व्यवस्था को देंगे आकार

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के जीएसटी विभाग में अब यह नई व्यवस्था प्रभावित की जा रही है, जिसमें रिवीजन के आदेश की समीक्षा की जाएगी। किस तरह की व्यवस्था को पहली बार आकार देने की कोशिश की जा रही है। जीएसटी विभाग में किसी भी फर्म पर जीएसटी चोरी का मामला सामने आने पर उसे पर टैक्स की राशि का अधिरोपण किया जाता है। कई बार ऐसा होता है जब संबंधित फार्म द्वारा विभाग की ओर से लगाई गई टैक्स की राशि को गलत ठहराते हुए रिवीजन के माध्यम से उस आदेश को चुनौती दी जाती



है। विभाग में यह नई व्यवस्था हो गई है कि रिवीजन के जो आवेदन लगाए जाते हैं, उन आवेदनों की ऑनलाइन सुनवाई किसी भी अधिकारी द्वारा की जाती है। इसमें आवेदन लगाने वाले व्यापारी अथवा व्यापारिक फार्म को यह मालूम नहीं पड़ता है कि उनके आवेदन की सुनवाई पूरे प्रदेश में कौन से स्थान पर पड़स्थ किस अधिकारी द्वारा की जा रही है, इस तरह की व्यवस्था को जीएसटी विभाग द्वारा आकार दिया जा चुका है।

एसटीएफ की तर्ज पर शस्त्र, वायरलेस सेट और आधुनिक वाहन देने की मांग

रेत माफिया से निपटने तैनात 34 वनरक्षक, हथियार और सुरक्षा उपकरण नहीं मिले

भोपाल। मुरैना में रेत माफिया पर कार्रवाई के लिए वन विभाग ने 34 वनरक्षकों को विशेष रूप से मुरैना वन मंडल सामान्य में पदस्थ किया है, लेकिन इन कर्मचारियों को आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त शस्त्र और आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने का मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश वन कर्मचारी मंच ने इस पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र भेजकर वनकर्मियों को पुलिस की एसटीएफ शाखा के समान सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाले वनकर्मियों लगातार जोखिम में काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें न तो पर्याप्त शस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं और न ही आत्मरक्षा के लिए आवश्यक



आधुनिक संसाधन। वन कर्मचारी मंच ने मुरैना वन मंडल के वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की घटना का हवाला देते हुए कहा कि रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी थी। संगठन का कहना है कि इस घटना ने वन कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। मंच के मुताबिक, इस मामले के बाद सर्वोच्च

न्यायालय ने रेत माफिया से निपटने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को शस्त्र, वायरलेस सेट और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के निर्देश दिए थे। संगठन का आरोप है कि इन निर्देशों के बावजूद राज्य में वन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अब तक प्रभावी व्यवस्था नहीं बन सकी है। बिना

हथियार माफिया का सामना करना मुश्किल मंच का कहना है कि रेत का अवैध कारोबार करने वाले गिरोह समंजित और आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे में वनकर्मियों को बिना सुरक्षा संसाधनों के उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजना उनकी जान को जोखिम में डालना है। संगठन के अनुसार, वन कर्मचारियों को शस्त्र देने के साथ उन्हें शस्त्र संचालन का अभिकार भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वायरलेस सेट, आधुनिक वाहन और अन्य हाईटेक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है, ताकि कार्रवाई के दौरान वनकर्मियों आपस में और पुलिस-प्रशासन के साथ तत्काल संपर्क कर सकें। एसटीएफ की तर्ज पर सुरक्षा व्यवस्था की मांग वन कर्मचारी मंच ने सरकार से मांग की है कि रेत

माफिया के खिलाफ अभियान में तैनात वनकर्मियों को पुलिस की एसटीएफ शाखा की तर्ज पर शस्त्र और सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। संगठन का कहना है कि केवल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से रेत माफिया पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकती, बल्कि उन्हें पर्याप्त अधिकार और संसाधन भी देने होंगे। मंच ने मुख्यमंत्री से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने और वन कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए तत्काल टोस नीति बनाने की मांग की है। वनकर्मियों की प्रमुख मांगें रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाले वनकर्मियों को शस्त्र उपलब्ध कराए जाएं। शस्त्र संचालन के लिए आवश्यक अधिकार और प्रशिक्षण दिया जाए। प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र में वायरलेस सेट उपलब्ध कराए जाएं।

माफिया के खिलाफ अभियान में तैनात वनकर्मियों को पुलिस की एसटीएफ शाखा की तर्ज पर शस्त्र और सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। संगठन का कहना है कि केवल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से रेत माफिया पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकती, बल्कि उन्हें पर्याप्त अधिकार और संसाधन भी देने होंगे। मंच ने मुख्यमंत्री से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने और वन कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए तत्काल टोस नीति बनाने की मांग की है। वनकर्मियों की प्रमुख मांगें रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाले वनकर्मियों को शस्त्र उपलब्ध कराए जाएं। शस्त्र संचालन के लिए आवश्यक अधिकार और प्रशिक्षण दिया जाए। प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र में वायरलेस सेट उपलब्ध कराए जाएं।

स्वातंत्र्यकारी मुद्रक और प्रकाशक शरद पाराशर द्वारा साईं प्रिंटेर्स म.नं. 19 शॉप नं. 3 जिंसी पुलिस चौकी के पास जहंगीरबाद, भोपाल म.प्र.से मुद्रित करवाकर ए-52 कस्तूरबा नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक- शरद पाराशर मो.9425023929, समाचार संपादक :-सेजल दौक्षित

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।)

भाजपा नए-युवा चेहरों पर लगाएगी दांव!

2027 के निकाय चुनाव से भाजपा की तैयारी शुरू, सीधे चुनाव से बदलेगा निकायों का राजनीतिक समीकरण



प्रकाशन कर चुका है। ऐसे में अब राजनीतिक दलों के पास चुनावी तैयारी के लिए स्पष्ट आधार उपलब्ध है। एंटी-इनकमबैंसी से निपटने युवा चेहरों पर भरोसा भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन निकायों में है, जहां वर्तमान अध्यक्षों और पार्षदों को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष की स्थिति बनी हुई है। पार्टी संगठन मानता है कि लंबे समय से पदों पर बने रहने वाले चेहरों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर एंटी-इनकमबैंसी पैदा हो सकती है। इसीलिए पार्टी सत्ता और संगठन में पीढ़ी परिवर्तन की रणनीति को निकाय चुनावों में भी लागू करने की तैयारी में है। 30 से 50 वर्ष आयु वर्ग के नेताओं को पार्षद पदों पर प्राथमिकता देने और अध्यक्ष-महापौर के लिए अपेक्षाकृत युवा चेहरों को सामने लाने पर विचार चल रहा है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अपवाद की गुंजाइश भी रखी जाएगी।

अविश्वास प्रस्ताव की अवधि

बढ़ाकर असंतोष थामने की कोशिश

नगरीय निकायों में अध्यक्षों के खिलाफ बढ़ते असंतोष और पार्षदों की गुटबाजी को नियंत्रित करने के लिए सरकार पहले ही अविश्वास प्रस्ताव के नियमों में बदलाव कर चुकी है। अस्थादेश और बाद में विधेयक के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष की गई। वर्ष 2024-25 में शिवपुरी और देवरी समेत करीब सौ निकायों में अध्यक्षों के खिलाफ पार्षदों का असंतोष सामने आया था। सरकार ने अवधि बढ़ाकर चुनाव से ठीक पहले संभावित राजनीतिक विद्रोह को रोकने की कोशिश की। इसके साथ ही अध्यक्ष को हटाने के लिए आवश्यक पार्षदों की संख्या भी बढ़ाई गई। पहले दो-तीन पार्षदों के समर्थन की आवश्यकता थी।

आमने-सामने की तैयारी

भाजपा के लिए 2027 के नगरीय निकाय चुनाव स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ और संगठन की ताकत परखने का मौका होगा। वहीं कांग्रेस इन्हीं चुनावों के राजनीतिक परिणामों और स्थानीय मुद्दों को 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए इस्तेमाल करने की रणनीति बना सकती है। इस तरह अगले वर्ष होने वाले निकाय चुनाव प्रदेश की राजनीति में सिर्फ स्थानीय सत्ता का चुनाव नहीं रहेंगे, बल्कि दोनों प्रमुख दलों के लिए 2028 की बड़ी चुनावी लड़ाई का सेमीफाइनल भी साबित हो सकते हैं।

मूसलाधार बारिश से घरों में घुसा पानी, गृहस्थी का सामान भीगा

राजधानी में आफत की बारिश: 50 से ज्यादा इलाकों में जलभराव

भोपाल। राजधानी में मानसून की तेज बारिश ने मंगलवार को शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। रातभर हुई तेज बारिश के बाद शहर के 50 से ज्यादा निचले इलाकों में जलभराव हो गया। कई स्थानों पर नाले उफनकर सड़कों पर आ गए, जबकि निचली बस्तियों और कॉलोनियों में घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया। सेमरा, शबरी नगर, कैलाश नगर, अशोका गार्डन, वसुंधरा कॉलोनी, जगदीशपुर, पटेल नगर, कॉन्स्ट्रीट ग्रीन कॉलोनी, साई बाबा रेजिडेंसी, मालीखेड़ी, जानकी अपार्टमेंट और अयोध्या बायपास सहित कई क्षेत्रों में लोग सुबह से पानी निकालने की जद्दोजहद करते नजर आए। भोपाल में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित सेमरा क्षेत्र रहा। यहां कुछ स्थानों पर घरों के आसपास करीब पांच फीट तक पानी भर गया। पानी घरों में घुसने से गृहस्थी का सामान भीगा गया। कई घरों में सांघ घुसने की भी सूचना रही, जबकि जलभराव के कारण सड़क पर खड़ी कारें आधी तक डूब गईं। सेमरा के हर निचले इलाके में पानी अशोका गार्डन से सेमरा की ओर जाने वाले रास्ते में पातरा नाला मुजरता



है। रात में हुई तेज बारिश के बाद नाला उफान पर आ गया। सुबह करीब पांच बजे से सेमरा के 500 से ज्यादा घरों के आसपास पानी भरना शुरू हो गया। लोग नींद से जागे तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। स्थानीय निवासी मनोज ठाकुर ने बताया कि सेमरा के लगभग हर निचले इलाके में पानी भर गया है। नाले के एक तरफ कुछ लोगों ने पहलें ही पांच से छह फीट ऊंचाई पर मकान बना लिए हैं, लेकिन तेज बारिश में उन घरों तक भी पानी पहुंच

गया। स्थानीय निवासी शेर सिंह ने कहा कि यह समस्या हर साल सामने आती है। मजदूर परिवारों के लिए बारिश के दौरान काम पर जाना मुश्किल हो जाता है। वहीं मनीष कुमार ने बताया कि नाले की सफाई ठीक से नहीं हुई है और उसमें कचरा भरा हुआ है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय वोट तो मांगते हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। घरों में घुटनों तक पानी, गृहस्थी का सामान

भीगा स्थानीय निवासी हेम बंसल ने बताया कि क्षेत्र में नाली और सड़क की उचित व्यवस्था नहीं है। जब भी तेज बारिश होती है, घरों में पानी भर जाता है। मंगलवार रात पानी घुटनों तक भर गया और परांग सहित गृहस्थी का सामान भीग गया। लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या नई नहीं है। हर साल बारिश के दौरान यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान के बजाय केवल अस्थायी राहत दी जाती है।

नालों की सफाई के दावों की खुली पोल

भोपाल में 100 से ज्यादा बड़े नाले हैं। मानसून से पहले नगर निगम और मौसम विभाग की ओर से नालों की सफाई के दावे किए गए थे। निगम की ओर से नालों की सफाई पूरी होने की बात भी कही गई थी, लेकिन करीब 24 घंटे की तेज बारिश ने इन दावों की हकीकत सामने ला दी। सेमरा से गुजरने वाले पातरा नाले की स्थिति इसका बड़ा उदाहरण रही। पुलिसिया के पास दाग, प्लास्टिक और अन्य कचरा जमा होने से नाले का पानी निकलने में परेशानी हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश से पहले निगम की टीम क्षेत्र में आई थी, लेकिन नाले की पर्याप्त सफाई नहीं की गई। रहवासियों का कहना है कि नालों में जमा कचरे के कारण पानी का बहाव रुक गया और देखते ही देखते पानी आसपास की बस्तियों में घुस गया। लोगों ने नगर निगम से नालों की नियमित सफाई और जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है।

एम्स भोपाल की नई जांच से एमडीआर-टीबी के इलाज में बड़ी राहत

अब 2 दिन में पता चलेगी कौन-सी दवा असरदार

भोपाल। दवा-प्रतिरोधी टीबी यानी एमडीआर-टीबी के मरीजों के इलाज में सही दवा चुनना बड़ी चुनौती है। अब एम्स भोपाल के विशेषज्ञों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। डॉक्टरों ने जीनोटाइप एमटीबीडीआरएसएल जांच विकसित की है, जिससे मरीज में दवा प्रतिरोध का पता करीब दो दिन में लगाया जा सकेगा। पहले ऐसी जांच की रिपोर्ट आने में चार से छह सप्ताह तक लग जाते थे। इस देरी के कारण डॉक्टरों को कई बार अनुमान के आधार पर उपचार शुरू करना पड़ता था। नई जांच से कम समय में यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि मरीज पर कौन-सी दवा प्रभावी रहेगी। 74 मरीजों पर किया गया अध्ययन एम्स के माइक्रोबायोलॉजी,



फेलोमरी मेडिसिन और ट्रांसलेशनल मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञों ने 74 एमडीआर-टीबी मरीजों पर इस जांच का परीक्षण किया। इसमें करीब 19 प्रतिशत मरीजों में फ्लोरोक्विनोलोन दवाओं के प्रति प्रतिरोध मिला। शोध में यह भी सामने आया कि दवा के असर को प्रभावित करने का एक कारण टीबी के जीवाणु में जीआर-ए जीन में बदलाव है। नई जांच ऐसे आनुवंशिक बदलावों की पहचान करने में मदद करती है। सरकार प्रयोगशालाओं में भी हो सकती है जांच इस तकनीक की खासियत यह है कि इसके लिए बहुत महंगी मशीन की जरूरत नहीं है।

साल का दूसरा एवं अंतिम सूर्यग्रहण 12-13 अगस्त की रात

4 घंटे 31 मिनट का होगा ग्रहण, मोक्ष की स्थिति 13 अगस्त को मध्य रात्रि 01:27:09 बजे पर

भोपाल। इस वर्ष का द्वितीय एवं अंतिम सूर्यग्रहण अमावस्या 12-13 अगस्त को होगा। यह पूर्ण सूर्यग्रहण होगा। भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण रात्रि 09:04:3 बजे से मध्य रात्रि 01:27:09 तक होगा। सूर्यग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होती है। सूर्यग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चन्द्रमा आ जाता है। बुधवार रात को खगोलीय घटना होने जा रही है। जो कि सूर्य ग्रहण के रूप में होगी। वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्त ने



बताया कि चन्द्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है जिससे कभी-कभी अमावस्या को पृथ्वी होता है। पूर्ण ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चन्द्रमा, पृथ्वी से पास की स्थिति में पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य आता है जिससे वह सूर्य को पूरा ढक लेता है। ग्रहण की अवधि 4 घंटे 31 मिनट तक रहेगी। भारत में इस समय रात्रि होने के कारण यह पूर्ण सूर्यग्रहण दृश्य नहीं होगा। यह सूर्यग्रहण पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैण्ड, उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर में बहुत अच्छी प्रकार से देखा जा सकेगा।

बजे से होगा। मध्य की स्थिति दिनांक 12 अगस्त 2026 को मध्य रात्रि 11:15:09 बजे पर होगी। इस समय सूर्य का 103.8 प्रतिशत भाग चंद्रमा के द्वारा ढक लिया जाएगा। जिससे कुछ समय के लिए अंधकार की स्थिति बन जाएगी। मोक्ष की स्थिति 13 अगस्त को मध्य रात्रि 01:27:09 बजे पर होगी। ग्रहण की अवधि 4 घंटे 31 मिनट तक रहेगी। भारत में इस समय रात्रि होने के कारण यह पूर्ण सूर्यग्रहण दृश्य नहीं होगा। यह सूर्यग्रहण पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैण्ड, उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर में बहुत अच्छी प्रकार से देखा जा सकेगा।